राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –109/2023
अन्तर्गत
अपील संख्या–388/2020

धीरज कुमार धाकड़

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर, राज.।
2. श्री राकेश लुहाड़िया, मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, सिविल लाईन्स, जयपुर।
3. श्री मुकेश बंसल, अधीक्षण अभियंता (Installation), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 16.05.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री युवराज सिंह राजावत, अभिभाषक
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 388/2020 में दिनांक 05.12.2022 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 05.12.2022 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :–

> 'प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी का नाम दिनांक 21.08.2019 से कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) की सूची में जोड़े जाने तथा तद्नुसार परिलाभ प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7330/2016 विमला देवी सैनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 को प्रदत्त निर्णय के अनुसार, जिसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) संख्या 26449/2020 द्वारा खारिज कर दी गई है, के अनुसार कार्यवाही हेतु

आदेशित करते हुए निवेदन किया गया। एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7330 / 2016 विमला देवी सैनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2017 पारित आदेश में अंकित किया गया है कि चारू जोशी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 419 / 2015 में आदेश दिनांक 22.01.2016 में यह निर्णीत किया गया है कि ''in the case of Charu Joshi Vs. State of Rajasthan & Ors.: SBCWP No. 419/2015, decided on 22nd January, 2016, after affording an opportunity of hearing to the counsel for the Staterespondents observing thus:

"5. I have heard learned counsel for the parties and have considered the facts of the case.

6. Rule 6 (1A) of the Rules of 1967 reads as under:- "6. Methods of Recruitment:- Recruitment to the Service after the commencement of these rules shall be made by the following methods in the proportion as indicated in column 3 of the schedule-

(a) direct recruitment in accordance with part IV of these rules, and

(b) Promotion (in accordance with Part V) of these rules): Provided-

(1) that if the Appointing Authority is satisfied in consultation with the Commission, where necessary, that suitable persons are not available for appointment by either method of recruitment in a particular year, appointment by the other method in relaxation of the prescribed proportion may be made in the same manner as specified in these rules; (1A) If a Diploma Holder Junior Engineer attains the qualifications of B.E. (Civil/Mechanical/Electrical), or AMIE, he shall be entitled on his application and subject to availability of vacancy, to be appointed as direct recruitment but in that case his seniority amongst the Junior Engineers(Degree Holders) shall be determined from the date of occurrence of vacancy against which such Junior Engineer has been appointed on the post of Junior Engineer (Degree Holder) and one third of his previous experience shall be counted as experience on the post of Junior Engineer for the purpose of promotion to the next higher post."

A reading of the aforesaid rule shows that a person who is Junior Engineer(Diploma Holder) attains the qualification of B.E. (Civil, Mechanical, Electrical or A.M.I.E.) shall be entitled, on an application, to be appointed as Junior Engineer(Degree Holder) by transfer against the quota of direct recruitment, but his case for seniority amongst the Junior Engineer(Degree Holder) shall be determined from the date of occurrence of vacancy with a further rider that 1/3rd of his previous experience shall be counted as experience on the post of Junior Engineer for the purpose of promotion to the next post.

7. This rule can be broken up into two segments, first being that if Junior Engineer (Diploma Holder) attains additional qualification, namely, B.E. (Civil, Mechanical, Electrical or A.M.I.E.), he can move an application to be appointed as Junior Engineer(Degree Holder) by way of transfer against the quota meant for direct recruitment of Degree Holders, but this would only be subject to availability of vacancy. The second limb of the rule pertains to, how the seniority is to be determined.

8. Admittedly, the petitioner was Diploma Holder in Civil Engineering on the date of submission of his application form, i.e. 30.6.2008. The interview was held on 23.5.2009 and appointment was offered on 17.9.2009. The additional qualification of A.M.I.E. was acquired subsequent to the date of

submission of application. Rule 6(1A) clearly specified that a Junior Engineer (Diploma Holder) who attains qualification of A.M.I.E. shall be entitled to be appointed as Junior Engineer (Degree Holder) by transfer against the quota of direct recruitment only on availability of vacancy. Reading of rule does not show that a only such Junior Engineer (Diploma Holder), can be considered for transfer to the quota of direct recruitment of Degree Holders if he has obtained degree while in service and after obtaining permission from the Department. Rule is silent to that effect and it certainly cannot be construed otherwise.

9. In the present case, the petitioner on the date of application was only had the qualification of Diploma Holder, even though he was undergoing A.M.I.E. Course and was in the final year. If the petitioner had applied, there was no guarantee that he would have qualified . The only surety, in his hands, was that he was a Diploma Holder and had a reasonable opportunity of being appointed as Junior Engineer(Diploma Holder). In case, he did not qualify in the degree course, he would have lost the opportunity under the Diploma quota as well. Rule 6(1A) only specifies that in case a Junior Engineer(Diploma Holder) attained qualification, he shall be entitled to be appointed as Junior Engineer(Degree Holder) by way of transfer against the quota of direct recruitment only on availability of a vacancy. Nonconsideration of his candidatures was on the ground that he did not apply in the advertisement under the Degree Holder quota and especially since he was already undergoing the third/final year examination is not tenable in view of the fact that the petitioner would be entitled to transfer only in case there is a vacancy and then of course the seniority would be reckoned as per rules.

10. In view of the above, the above noted writ petition is allowed with the direction to the respondent to consider the case of the petitioner for transfer in the quota of direct recruitment of Junior Engineer(Degree Holder) by way of transfer in case there is a vacancy and to compute his seniority according to the Rules. "

हस्तगत अपील के तथ्य भी उक्त रिट पिटीशन के तथ्यों के अनुरूप ही है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन में दिए गए निर्णय के अनुसार हस्तगत प्रकरण में भी कार्यवाही किया जाना उचित है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त निर्णय की रोशनी में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा निर्देश दिए जाते है कि हस्तगत अपील में विमला देवी सैनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7330/2016 के आदेश दिनांक 22.01.2016 में पारित निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे। उक्त कार्यवाही उक्त आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत किए जाने की चार माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आदेश आज दिनांक 05.12.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।"

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 05.12.2022 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। प्रत्यर्थीगण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं

कर रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 05.12.2022 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से अवमानना प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायलय में प्रस्तुत एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 20479/2023 उनवानी जरिये प्रमुख सचिव, पीएचईडी, जयपुर एवं अन्य बनाम धीरज कुमार धाकड में पारित निर्णय तक विचाराधीन रखे जाने हेतु निवेदन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के आदेश के सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में हम पाते हैं कि अधिकरण के आदेश की पालना किया जाना प्रत्यर्थी विभाग के लिये बाध्यकारी था।

4. हमनें उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति की।

5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :–

> "प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी का नाम दिनांक 21.08.2019 से कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) की सूची में जोड़े जाने तथा तदनुसार परिलाभ प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7330/2016 विमला देवी सैनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 को प्रदत्त निर्णय के अनुसार, जिसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) संख्या 26449/2020 द्वारा खारिज कर दी गई है, के अनुसार कार्यवाही हेतु आदेशित करते हुए निवेदन किया गया। एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7330/2016 विमला देवी सैनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2017 पारित आदेश में अंकित किया गया है कि चारू जोशी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 419/2015 में आदेश दिनांक 22.01.2016 में यह निर्णीत

किया गया है कि ''in the case of Charu Joshi Vs. State of Rajasthan & Ors.: SBCWP No. 419/2015, decided on 22nd January, 2016, after affording an opportunity of hearing to the counsel for the Staterespondents observing thus:

"5. I have heard learned counsel for the parties and have considered the facts of the case.

6. Rule 6 (1A) of the Rules of 1967 reads as under:- "6. Methods of Recruitment:- Recruitment to the Service after the commencement of these rules shall be made by the following methods in the proportion as indicated in column 3 of the schedule-

(a) direct recruitment in accordance with part IV of these rules, and

(b) Promotion (in accordance with Part V) of these rules): Provided-

(1) that if the Appointing Authority is satisfied in consultation with the Commission, where necessary, that suitable persons are not available for appointment by either method of recruitment in a particular year, appointment by the other method in relaxation of the prescribed proportion may be made in the same manner as specified in these rules; (1A) If a Diploma Holder Junior Engineer attains the qualifications of B.E. (Civil/Mechanical/Electrical), or AMIE, he shall be entitled on his application and subject to availability of vacancy, to be appointed as direct recruitment but in that case his seniority amongst the Junior Engineers(Degree Holders) shall be determined from the date of occurrence of vacancy against which such Junior Engineer has been appointed on the post of Junior Engineer (Degree Holder) and one third of his previous experience shall be counted as experience on the post of Junior Engineer for the purpose of promotion to the next higher post."

A reading of the aforesaid rule shows that a person who is Junior Engineer(Diploma Holder) attains the qualification of B.E. (Civil, Mechanical, Electrical or A.M.I.E.) shall be entitled, on an application, to be appointed as Junior Engineer(Degree Holder) by transfer against the quota of direct recruitment, but his case for seniority amongst the Junior Engineer(Degree Holder) shall be determined from the date of occurrence of vacancy with a further rider that 1/3rd of his previous experience shall be counted as experience on the post of Junior Engineer for the purpose of promotion to the next post.

7. This rule can be broken up into two segments, first being that if Junior Engineer (Diploma Holder) attains additional qualification, namely, B.E. (Civil, Mechanical, Electrical or A.M.I.E.), he can move an application to be appointed as Junior Engineer(Degree Holder) by way of transfer against the quota meant for direct recruitment of Degree Holders, but this would only be subject to availability of vacancy. The second limb of the rule pertains to, how the seniority is to be determined.

8. Admittedly, the petitioner was Diploma Holder in Civil Engineering on the date of submission of his application form, i.e. 30.6.2008. The interview was held on 23.5.2009 and appointment was offered on 17.9.2009. The additional qualification of A.M.I.E. was acquired subsequent to the date of submission of application. Rule 6(1A) clearly specified that a Junior Engineer (Diploma Holder) who attains qualification of A.M.I.E. shall be entitled to be appointed as Junior Engineer (Degree Holder) by transfer against the quota of direct recruitment only on availability of vacancy. Reading of rule does not show that a only such Junior Engineer (Diploma Holder), can be considered for transfer to the quota of direct recruitment of Degree Holders if he has obtained

degree while in service and after obtaining permission from the Department. Rule is silent to that effect and it certainly cannot be construed otherwise.

9. In the present case, the petitioner on the date of application was only had the qualification of Diploma Holder, even though he was undergoing A.M.I.E. Course and was in the final year. If the petitioner had applied, there was no guarantee that he would have qualified . The only surety, in his hands, was that he was a Diploma Holder and had a reasonable opportunity of being appointed as Junior Engineer(Diploma Holder). In case, he did not qualify in the degree course, he would have lost the opportunity under the Diploma quota as well. Rule 6(1A) only specifies that in case a Junior Engineer(Diploma Holder) attained qualification, he shall be entitled to be appointed as Junior Engineer(Degree Holder) by way of transfer against the quota of direct recruitment only on availability of a vacancy. Nonconsideration of his candidatures was on the ground that he did not apply in the advertisement under the Degree Holder quota and especially since he was already undergoing the third/final year examination is not tenable in view of the fact that the petitioner would be entitled to transfer only in case there is a vacancy and then of course the seniority would be reckoned as per rules.

10. In view of the above, the above noted writ petition is allowed with the direction to the respondent to consider the case of the petitioner for transfer in the quota of direct recruitment of Junior Engineer(Degree Holder) by way of transfer in case there is a vacancy and to compute his seniority according to the Rules. "

हस्तगत अपील के तथ्य भी उक्त रिट पिटीशन के तथ्यों के अनुरूप ही है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन में दिए गए निर्णय के अनुसार हस्तगत प्रकरण में भी कार्यवाही किया जाना उचित है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त निर्णय की रोशनी में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा निर्देश दिए जाते है कि हस्तगत अपील में विमला देवी सैनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7330/2016 के आदेश दिनांक 22.01.2016 में पारित निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे। उक्त कार्यवाही उक्त आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत किए जाने की चार माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आदेश आज दिनांक 05.12.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।''

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी–अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी है, परंतु अभी तक अधिकरण के आदेश दिनांक 05.12.2022 की क्रियान्विति को स्थगित नहीं करवाया है। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः

अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के **सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151)** के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :–

> *"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86)** में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :–

> *"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन **मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030)** में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :–

> *"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण–

प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 05.12.2022 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी–अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)